हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

मारवाड़ का मित्र

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post Reg No. RJ/SRO/9657/2023-25 www.marwadkamitra.in twitter.com/MARWADKAMITRA facebook.com/marwarkamitra/ youtube.com/c/mkmnewsnetwork

वर्ष 22 | अंक 17 | सांचौर, रविवार , 1, सितंबर 2024 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव, | मूल्य वार्षिक 350 रुपये | कुल पृष्ठ - 4

राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना पोर्टल की हुई शुरुआत

गोपालक किसान अब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर सकेंगे ऋण के लिये आवेदन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों और पशुपालकों की समृद्धि और कल्याण के लिये कृतसंकल्प है और इसी सोच को साकार करने के लिये राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल की शुरूआत की गई है। नेहरू सहकार भवन में आयोजित समारोह में पोर्टल की शुरूआत करते हुये श्री दक ने कहा कि देश में पहली बार राजस्थान प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत गोपालक किसान परिवार को एक लाख रुपये तक का अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण एक वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि गोपालक किसान द्वारा ऋण का समय पर चुकारा करने पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि गोपालक किसान परिवारों को गाय/भैंस हेतु शैड, खेली निर्माण एवं चारा/बांटा सहित आवश्यक उपकरण खरीदने के लिये पैसों की कमी रहती थी, जिससे वह गोपालन से मिल सकने वाला पूरा लाभ नहीं ले पाता था। इसी को ध्यान में रखते हुये गोपालक किसान को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश के अधिकाधिक गोपालक किसानों को गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने के लिये दुग्ध संघ एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संयुक्त तत्वाधान में शिविरों का आयोजन किया जायेगा ताकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये पांच लाख किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों से कहा कि योजना का अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के लिये योजना का प्रचार-प्रसार किया जावे। इस अवसर पर शासन सचिव, सहकारिता श्रीमती शुचि त्यागी, रजिस्ट्रार, सहकारिता श्रीमती अर्चना सिंह, प्रबंध निदेशक आरसीडीएफ श्रीमती सुषमा अरोडा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) श्री राजीव लोचन शर्मा, प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक श्री संजय पाठक सहित सहकारिता विभाग तथा आरसीडीएफ और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

1 लाख रुपये तक का मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण

5 लाख पशुपालक किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण

1 वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध कराया जायेगा ब्याज मुक्त ऋण

ऋण स्वीकृति की सपूर्ण प्रक्रिया को बनाया गया है पूर्ण पारदर्शी

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने कहा कि ऋण वितरण को पारदर्शी बनाने तथा गोपालक किसान परिवार को ऋण प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसलिये ऋण आवेदन से लेकर स्वीकृति की प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से संपादित किया जायेगा। गोपालक किसान ई-मित्र केन्द्र या संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से ऋण के लिये आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि गोपालक किसान को प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य होना अनिवार्य है।

भारी बारिश से बर्बाद हुई फसलों की गिरदावरी के आदेश जारी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर. राजस्थान में बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण कई इलाकों में फसलें बर्बादी के कगार पहुंच गई हैं. इससे आहत हुए किसानों को राहत देने के लिए सूबे की भजनलाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्व विभाग ने अतिवृष्टि वाले सभी इलाकों की गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं. इससे किसानों को मुआवजा मिलने की उम्मीद बंधी है. सीएम के निर्देश के बाद राजस्व विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र जारी कर अपने-अपने जिलों में अतिवृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान की आंकलन करने के आदेश दे दिए हैं. राजस्थान में भारी बारिश से कई जिलों में जलभराव के कारण किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं. कई इलाकों में अभी भी खेतों में पानी भरा होने के कारण किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है. अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के बाद किसानों की समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, विधायकों और सांसदों ने राज्य सरकार से गिरदावरी रिपोर्ट करने के लिए पत्र लिखे हैं. जनप्रतिनिधियों के साथ साथ ही मौसम विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, सहकारिता विभाग और नाबार्ड के अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर खरीफ की फसलों के खराबे का आंकलन कर किसानों को राहत पहुंचाने की जरुरत मानी गई है.

खरीफ की फसलों की रिकॉर्ड बुवाई की गई है

कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस बार राजस्थान में खरीफ की फसलों की रिकॉर्ड बुवाई हुई है. राजस्थान में वर्ष 2024 में खरीफ फसल की बुवाई 15560 हजार हैक्टेयर पर की गई है. कृषि विभाग के अनुसार इस बार बाजरा 4250.33 हजार हैक्टेयर, मक्का- 962.40 हजार हैक्टेयर, स्पेशल मिलेट्स- 2.66 हजार हैक्टेयर और ज्वार की 642 हजार हैक्टेयर में बुवाई की गई है.

दलहन और तिलहन का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन

वहीं दलहन में मूंग- 2253.61 हजार हैक्टेयर, मोठ- 899.28 हजार हैक्टेयर, उड़द- 297.41 हजार हैक्टेयर, चौला- 55.31 हजार हैक्टेयर, रहर- 8.20 हजार हैक्टेयर में बोई गई है. तिलहन में तिल- 205.38 हजार हैक्टेयर, मूंगफली- 860 हजार हैक्टेयर और सोयाबीन- 1123 हजार हैक्टेयर में बोया गया है. अन्य फसलों में कॉटन- 515 हजार हैक्टेयर, गन्ना- 5.11 हजार हैक्टेयर, ग्वार- 2710.44 हजार हैक्टेयर और शेष अन्य फसलें 386 हजार हैक्टेयर में बोई गई हैं.

धान बोआई के रकबे में छह प्रतिशत की बढ़ोतरी

नई दिल्ली ; चालू 2024-25 खरीफ सत्र में अब तक धान की बोआई का रकबा छह प्रतिशत बढ़कर 369.05 लाख हेक्टेयर हो गया है। एक साल पहले की समान अवधि में धान का रकबा 349.49 लाख हेक्टेयर था। 20 अगस्त तक दलहन बोआई का रकबा बढ़कर 120.18 लाख हेक्टेयर हो गया, जो पिछले साल 113.69 लाख हेक्टेयर था।

2 से 9 सितंबर तक करवा सकते हैं बच्चों के आधार अपडेशन

पाली । सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के निर्देशानुसार 02 सितम्बर से 09 सितम्बर 2024 तक (राजकीय अवकाश का छोड़कर) 5-15 वर्ष एवं 15+ वर्ष के आयु वर्ग के आधार में मेनडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट से शेष रहे बच्चों के लिए पाली पंचायत समिति क्षेत्र के चार स्थानों पर आधार शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने बताया कि पाली क्षेत्र के भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र कलक्ट्रेट परिसर पाली, पंचायत समिति पाली, ग्राम पंचायत भांगेसर एवं ग्राम पंचायत खैरवा में शिविर आयोजित होंगे। इन शिविरों में पाली शहर / ग्रामीण में स्थित 5-15 एवं 15+ के आयु वर्ष के बच्चों का जिनका बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ है। वे सभी अपना आधार कार्ड लेकर इन आधार शिविर स्थल पर पहुँचकर आधार में मेनडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट करवा सकते है।

चार दिवसीय पशुधन गणना प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन

जयपुर,। भारत सरकार द्वारा सितंबर, 2024 से दिसंबर, 2024 तक 21वीं अखिल भारतीय पशुधन गणना का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। जिसके तहत जिला-जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली-बहरोड़ के पर्यवेक्षकों एवं प्रगणकों के लिए चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।

राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल का शुभारम्भ

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बारां,। प्रबन्ध निदेशक केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, सौमित्र कुमार मंगल ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा बिन्दु संख्या 24 अन्तर्गत राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल का शुभारम्भ आज 28 अगस्त 2024 को माननीय सहकारिता मंत्री गौतम दक द्वारा किया गया। इस योजनान्तर्गत गोपालक परिवार ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन कराकर डेयरी से संबंधित गतिविधियों यथा गौवंश हेतु शेड, खेली का निर्माण, दुग्ध, चारा, बाटा संबंधी उपकरण खरीदने हेतु 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते है। इस योजनान्तर्गत बारां जिले को 8 320 गोपालक परिवारों को ऋण दिए जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

गांव और गरीब के लिए सदा समर्पित होकर कार्य करता रहूंगा : राज्यपाल

जयपुर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का सहकार महर्षि के रूप में छत्रपति संभाजी नगर में महाराष्ट्र के डेयरी और राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील के मुख्य आतिथ्य में जनप्रतिनिधियों, सहकारिता आंदोलन से जुड़े लोगों व आम जन ने अभिनंदन किया। यह कार्यक्रम गौसंवर्धन दुग्ध सहकारी संस्था के स्वर्ण जयंती महोत्सव पर आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बागड़े भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि वह डेयरी, पशुपालन और सहकारिता के जरिए गांव व गरीब के लिए सदा समर्पित होकर कार्य करते रहेंगें। उन्होंने कहा कि यह मेरा नहीं जनता का सम्मान है। गौरतलब है कि बागड़े ने दुग्ध उत्पादन और विपणन के जरिए पशुपालकों और किसानों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया था।

सहायक रजिस्ट्रार पद पर पदोन्नत हुए निरीक्षक मरड़िया

जयपुर,। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में सहकारी विभाग में कार्यरत राजस्थान सहकारिता

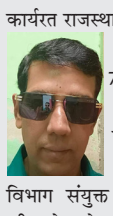

राज्य सेवा के 75 अधिकारियों को पदोन्नत करने के पश्चात सहकारिता विभाग संयुक्त शासन सचिव की ओर से पदोन्नति आदेश जारी कर दिए गए है, जिसमें सहकारिता सेवा के निरीक्षक ग्रेड प्रथम ऋषभ मरड़िया को सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति दी गई है।

दो वर्ष की डीपीसी हुई सपन्न

राजस्थान सहकारिता सेवा के 75 अधिकारी हुए पदोन्नत

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । *राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में सहकारी विभाग में कार्यरत राजस्थान सहकारिता राज्य सेवा के 75 अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है। वर्ष 2023-24 में सहकारिता सेवा के 29 अधिकारियों एवं 2024-25 में 46 अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है। वर्ष 2023-24 के लिये संयुक्त रजिस्ट्रार से अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पद पर 1, उप रजिस्ट्रार से संयुक्त रजिस्ट्रार के पद पर 2, सहायक रजिस्ट्रार से उप रजिस्ट्रार के पद पर 9 तथा सहकारी निरीक्षक से सहायक रजिस्ट्रार के पद पर 17 अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिये अतिरिक्त रजिस्ट्रार से अतिरिक्त रजिस्ट्रार (सीनियर स्केल) के पद पर 3, संयुक्त रजिस्ट्रार से अतिरिक्त रजिस्टार के पद पर 7, उप रजिस्ट्रार से संयुक्त रजिस्ट्रार के पद पर 10, सहायक रजिस्ट्रार से उप रजिस्ट्रार के पद पर 11 तथा सहकारी निरीक्षक से सहायक रजिस्ट्रार के पद पर 15 अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है। संयुक्त रजिस्ट्रार तथा सहायक रजिस्ट्रार के एक-एक पद के लिये रिव्यू डीपीसी भी गई। माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में उद्योग विभाग से सहकारिता विभाग में समायोजित किये गये निरीक्षकों की रिव्यू डीपीसी भी आयोजित की गई।*

हार्दिक बधाई

श्रीमान् ऋषभ मरड़िया
कार्यकारी निरीक्षक पद
से सहायक रजिस्ट्रार,
सहकारिता सेवा के पद पर
पदोन्नति होने पर हार्दिक
बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं

शुभेच्छु

नीतिराजसिंह भाटी, ब्लॉक अध्यक्ष
एवं समस्त पदाधिकारी गण राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ, ब्लॉक इकाई जसवंतपुरा, जिला-जालोर

जीएसएस व्यवस्थापकों की शाखावार आयोजित होगी बैठक

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । *जिले में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की बैठक का आयोजन केंद्रीय सहकारी बैंक की विभिन्न शाखाओं में किया जाएगा, इसके लिए सीसीबी प्रबंध निदेशक की ओर से शाखा प्रबंधक एवं ऋण पर्यवेक्षक को निर्देशित किया हैं कि 2 सितम्बर को जालोर, आहोर, 3 सितम्बर को सायला, मेंगलवा, 4 सितम्बर को धुम्बड़िया, भीनमाल, 5 सितम्बर को अरणाय, चितलवाना, सांचौर, 6 सितम्बर को रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, रामसीन शाखा परिसर में बैठक आयोजित की जाएगी । वही, आयोजित बैठक में खरीफ ऋण वितरण, अवधिपार ऋण, चालू ऋणों की मांग, ग्राम सेवा सहकारी समितियों की ऑडिट और एनपीए ऋणों की वसूली प्रगति, पैक्स कंप्यूटराईजेशन, सीएससी, पीडीएस, गोदाम एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गबन, अनियमितताओं की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।*

सहकारी समितियों में अटकी ब्याज अनुदान की राशि

व्यवस्थापकों की जेब व सहकारी समितियों के कोष पर भारी पड़ रही ब्याज मुक्त योजना

जिले की 200 से ज्यादा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में संस्थापन व्यय तक हुआ मुश्किल

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । जिले सहित प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए ब्याज मुक्त योजना में देय ब्याज अनुदान की राशि व्यवस्थापकों एवं सहकारी समितियां के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गई है। दरअसल, सहकारिता विभाग ने मौजूदा वित्तीय वर्ष तो दूर पिछले वित्तीय वर्ष की जनवरी 2023 से ब्याज मुक्त योजना के तहत देय ब्याज अनुदान की राशि अब तक जारी नहीं की है। जिसके चलते जिले की करीब-करीब ग्राम सेवा सहकारी समितियों में लाखों रुपए की राशि अटक गई है। इसके चलते कई सहकारी समितियों में अन्य विविध व्यवसाय पर बजट अभाव में ब्रेक लग गए हैं तो कहीं सहकारी समितियों का संचालन अपनी निजी पूंजी से करने वाले व्यवस्थापकों की जेब भी जवाब दे गई हैं

यह है योजना

राज्य सरकार की ओर से शुन्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्प समय पर रबी एवं खरीफ सीजन में फसली सहकारी ऋण ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता हैं, एवं दोनो सीजन में समय पर फसली ऋण का चुकारा करने पर राज्य सरकार की ओर से 4 प्रतिशत एवं भारत सरकार की ओर से 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता हैं, यह ब्याज अनुदान राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से केंद्रीय सहकारी बैंक को मिलता हैं, इसी अनुदान में से 2 प्रतिशत राशि पैक्स-लैंपस को दिए जाने का प्रावधान है।

कई समितियों में व्यवसाय सुविधा प्रभावित

जिले की करीब-करीब सहकारी समितियों में खाद-बीज क्रय-विक्रय का व्यवसाय किया जा रहा हैं, पर ब्याज मुक्त योजना की एवज में मिलने वाली ब्याज अनुदान राशि का भुगतान समय पर नहीं होने के चलते खाद-बीज क्रय व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। जिसका असर सहकारी समिति से जुड़े किसानों पर पड़ रहा हैं और किसानों को बाजार से सीजन के दौरान निजी कंपनियों की खाद-बीज की खरीदारी करनी पड़ रही हैं,

जेब से लाखों खर्च, कहीं बढ़ा कर्ज

जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सहकारी पोर्टल संचालन करने के लिए बैंक अकाउंट में एडवांस बजट बनाए रखने के लिए बहुत सी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापक अपनी जेब से बजट राशि भर रहें है, तो कई सहकारी समितियां के व्यवस्थापक गांवों के ही साहुकारों से कर्ज लेकर सहकारी पोर्टल का संचालन कर रहें है। जबकि बजट के अभाव में जिले की करीब-करीब सहकारी समितियों के लिए पोर्टल का संचालन गले की फांस बनकर रह गया है।

इनका कहना है...

ब्याज मुक्त योजना के तहत दिसंबर 2022 के बाद से ब्याज अनुदान की राशि जारी नहीं होने से जालोर सहित प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवसास एवं संस्थापन व्यय प्रभावित हुआ है। सरकार को योजना की जल्द ही बकाया ब्याज अनुदान की राशि जारी करनी चाहिए।

-हनुमानसिंह राजावत,
जिला अध्यक्ष, व्यवस्थापक यूनियन जालोर

ब्याज मुक्त योजना के तहत देय ब्याज अनुदान की राशि के लिए उच्च अधिकारियों से संपर्क किया है। योजना की राशि जब भी जारी होगी, समितियों के खातों में जमा कर दी जाएगी ।

सीसीबी बैंक प्रबंधन जालोर

परेशानियां बढ़ाने वाले हैं स्कूली शिक्षा में नित नए फरमान

सरकार बदलने के साथ ही नियम-कायदे भी बदलने की सबसे ज्यादा बातें शिक्षा महकमे में होती आई है। स्कूली शिक्षा में यह ज्यादा ही होता रहा है। तभी तो नए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कभी अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों की समीक्षा करने, कभी शिक्षकों के लिए कार्यस्थल पर मोबाइल के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने तो कभी अधिशेष शिक्षको के समायोजन को लेकर नए कायदे लागू करने की बाता कहने में कमी नहीं रखी। यह बात दूसरी है कि दिशानिर्देशों की विसंगतियों ने पढ़ाई-लिखाई की बेहतर व्यवस्था करने के बजाय अफसरों को इस बात में ज्यादा उलझाए रखा कि बार-बार बदलने वाले आदेशों को आखिर कैसे लागू किया जाए? अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों पर मंत्री के बयान से असमंजस में आए कई अभिभावकों को समझ में ही नहीं आया कि ये स्कूल जारी रहेंगे अथवा इनमें से कुछ बंद हो जाएंगे। विरोधाभास की हद यह कि सरकार इन्हीं अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भर्ती करने में जुटी है। ऐसा ही असमंजस स्कूलों में मोबाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को लेकर हुआ। शिक्षा विभाग के कई ऑनलाइन कामकाज में बाधा आने की बात सामने आने पर यह मंत्री का यह फरमान भी लागू नहीं हो पाया। अधिशेष शिक्षकों के समायोजन प्रक्रिया को भी इतना जटिल बना दिया गया है कि समस्या कम होने के बजाया बढ़ती ही जा रही है। स्कूलों में छात्र-छात्राओं के नामांकन के अनुपात में शिक्षक तैनात हों, यह ज्यादा जरूरी है। लेकिन, इस दिशा में काम नहीं हो पा रहा। वस्तुत: जितना बड़ा शिक्षा महकमा है, उसके हिसाब से नीतियों के क्रियान्वयन की तैयारी नहीं हो पा रही। कहीं जरूरत से ज्यादा शिक्षक हैं तो कहीं बच्चों की संख्या के हिसाब से शिक्षकों के पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं। समायोजन के काम में भी राजनीतिक दखलंदाजी होने लगे तो पारदर्शिता कहां रहेगी? अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों के लिए भी स्पष्ट और स्थायी नीति बनानी होगी ताकि अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग के बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मिल सके। शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कर उन्हें शिक्षा के मूल कार्य पर लगाना भी जरूरी है। शिक्षा व्यवस्था को प्रयोगशाला बनाने के बजाय सुधार के लिए विद्यालय विकास समितियों और अभिभावकों को भी साथ लेना होगा। तब जाकर ही सरकारी स्कूलों का कायापलट हो सकेगा।

सहकारी क्षेत्र में नई जान फूंकते पैक्स

-शाजी के. वी.
अध्यक्ष - राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक(नाबार्ड)

दुनिया भर में 'अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025' के स्वागत की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। यह ऐसे समय में हो रहा है, जब भारत का सहकारिता क्षेत्र मजबूत स्थिति में है और देशभर में नई, मजबूत एवं तेजी से उभरती हुई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी पैक्स का प्रसार हो रहा है। आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों से लैस ये पैक्स अब ग्रामीण और कृषि प्रधान भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यद्यपि भारत में सहकारिता का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन कुप्रबंधन, संकट के समय पर्याप्त सरकारी समर्थन की कमी और आवश्यक सुधारों की अनुपस्थिति के कारण इसका विकास बाधित रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल में सहकारिता मंत्रालय का गठन करने और गृहमंत्री अमित शाह को इसकी कमान सौंपने के तुरंत बाद सहकारिता क्षेत्र में बदलाव की बयार बहने लगी। सहकारिता की क्षमता को अब देश के भविष्य को आकार देने वाले क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। अमित शाह सहकारिता क्षेत्र के पुराने जानकार हैं। वह सहकारिता क्षेत्र के विकास में बाधा डालने वाले कारणों से अच्छी तरह परिचित हैं। इन बाधाओं में पैक्स के विविधीकरण की कमी थी, जिसने उन्हें लगभग अव्यवहार्य बना दिया था। अमित शाह ने पैक्स के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया, वह उनके बायलाज यानी उप-नियमों में बदलाव लाना था। पैक्स की समस्याओं से छुटकारे के लिए माडल बायलाज लाकर उन्हें बहुद्देश्यीय बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे पैक्स को अपने व्यवसाय को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़कर विविधता लाने में मदद मिली है। अब वे कामन सर्विस सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं, जो ग्रामीण भारत में 300 से अधिक ई-सेवाएं जैसे-बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अपडेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, पैन कार्ड और आइआरसीटीसी/बस/हवाई टिकट आदि सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अब तक 35,000 से अधिक पैक्स ने ग्रामीण नागरिकों को ये सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अब उन्हें प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जल समितियों, एलपीजी वितरकों, खुदरा पेट्रोल/डीजल दुकानों, किसान उत्पादक संगठनों आदि के रूप में कार्य करने में भी सक्षम बनाया जा रहा है। पैक्स अब गांवों में सस्ती दरों पर गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के वितरण के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में भी काम कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण आबादी के लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध कराते हुए आय का एक और स्रोत पैदा हो रहा है। ये सभी प्रयास पैक्स की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए किए जा रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय का अगला महत्वपूर्ण कार्य इस क्षेत्र में लोगों का विश्वास जीतना है, जो दशकों से कुप्रबंधन से ग्रस्त था। इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 63,000 पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। अब तक 23 हजार से अधिक पैक्स को एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग साफ्टवेयर के साथ एकीकृत किया भी जा चुका है।

पैक्स के कंप्यूटरीकरण से उन्हें सीधे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड से जोड़ा जा सकेगा। कामन अकाउंटिंग सिस्टम और मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम से संचालन में एकरूपता आएगी। इससे पैक्स संचालन में जनता का विश्वास बढ़ेगा। सहकारिता क्षेत्र में हुई इन अनूठी पहलों से यह क्षेत्र अब नए आत्मविश्वास के साथ पूरे देश में संगठित रूप में काम कर रहा है, जो इसके लिए बहुत फायदेमंद है। सहकारिता मंत्री के रूप में अमित शाह ने अब सहकारी क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों से जिला सहकारी बैंकों में बैंक खाते खोलने का आह्वान किया है, ताकि उन्हें व्यवहार्य बनाया जा सके। उनके अनुसार, सहकारी समितियों के बीच सहयोग एक मजबूत आर्थिक सिद्धांत है, जो मजबूत सहकारी क्षेत्र के निर्माण के लिए जरूरी है। वर्ष 2024 में सहकारिता मंत्रालय का दूसरी बार कार्यभार संभालते हुए अमित शाह ने जमीनी स्तर पर नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करके इस क्षेत्र को मजबूत करने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके पिछले कार्यकाल में नीतिगत ढांचा बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था और वर्तमान कार्यकाल में उनकी प्राथमिकता इन नीतियों को जमीनी स्तर तक ले जाने की होगी। सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण पहल में से एक सहकारी क्षेत्र में 'विश्व का सबसे बड़ा विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण कार्यक्रम' है। इस योजना का उद्देश्य पैक्स स्तर पर अनाज भंडारण के लिए विकेंद्रीकृत गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां और अन्य कृषि अवसंरचनाएं बनाना है। इन गोदामों का उद्देश्य कृषि और इससे जुड़े कामों के लिए इस्तेमाल करना है। कृषि अवसंरचना कोष, कृषि विपणन अवसंरचना, कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण आदि सरकार की विभिन्न कार्यक्रमों को मिलाकर इस योजना का उद्देश्य देश के लिए एक विशाल भंडारण क्षमता का निर्माण करना है। इससे खाद्यान्न की बर्बादी और परिवहन लागत में कमी आएगी, किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम मिलेंगे और विभिन्न कृषि जरूरतों को पैक्स स्तर पर ही पूरा किया जा सकेगा। चूंकि पैक्स ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं। इसलिए इनके सुदृढ़ीकरण और पुनरुद्धार से बहुत जल्द ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा मिलेगा। पैक्स से जुड़ी गतिविधियों के बढ़ने से जहां मौसमी बेरोजगारी खत्म होने की उम्मीद की जा रही है, वहीं इससे करीब एक लाख पैक्स से सीधे जुड़े 13 करोड़ किसानों को विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय सृजन में फायदा होगा।

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

> **पैक्स ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं। इसलिए इनके सुदृढ़ीकरण और पुनरुद्धार से बहुत जल्द ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा मिलेगा। पैक्स से जुड़ी गतिविधियों के बढ़ने से जहां मौसमी बेरोजगारी खत्म होने की उम्मीद की जा रही है वहीं इससे करीब एक लाख पैक्स से सीधे जुड़े 13 करोड़ किसानों को विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय सृजन में फायदा होगा।**

कृषि; कृषक परिवार जिन वस्तुओं का निर्माण करें, उनकी बिक्री की व्यवस्था हाट बाजारों में की जा सकती है

ग्रामीण उद्योगों को बनाएं किसानों की ताकत

कृषकों की आय बढ़ाने के लिए कम पानी में पैदा होने वाली फसलों पर अधिक से अधिक ध्यान देना जरूरी है। साथ ही ग्रामीण उद्योगों का विकास करके भी कृषकों की आय को बढ़ाने के प्रयास किए जा सकते हैं।

भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि और किसानों की उपेक्षा करके भारत विकसित देश नहीं बन सकता। यही वजह है कि केंद्र सरकार कृषि के विकास और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के प्रयास कर रही है। इसके बावजूद इस दिशा में अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सदियों से भारत में कृषि एक एकीकृत सेक्टर के रूप में रही है। हमारे यहां खेतों का आकार छोटा होने पर भी कृषक आमतौर पर सुखी था। सिंचाई की व्यवस्था अपर्याप्त होने पर भी किसान एक फसल उगाते हुए, खाली समय में पशु पालन करता था। उसके पास प्राय; गाय, कुछ भेड़-बकरियां या दूसरे पशु हुआ करते थे, जिनसे उसे अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती थी। कुछ किसान बढ़ई, मोची, लुहार का काम भी करते थे, तो कुछ रस्सी बनाने का कार्य करते थे। इन गतिविधियों से अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती थी। इस स्थिति में धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ। शहरों के विकास के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति समीपवर्ती कस्बों से होने लगीं। इनमें बढ़ई का सामान, जूते-चप्पल, साबुन, रस्सी, खाद्य सामग्री, दालें तथा अन्य खुदरा वस्तुएं शामिल थीं। इस कारण हमारे गांव के छोटे किसान अतिरिक्त आय से वंचित होने लगे। उनके रोजगार तथा आय के स्तर में कमी हो गई, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां केवल एक ही फसल उगाई जा रही थी। साथ ही गांव की स्वायत्तता भी समाप्त होती गई। वस्तुत; अनेक पीढ़ियों से भारत का किसान अनेक गतिविधियों का संचालन एक साथ करता रहा है। परिवार के लिए भरण पोषण के लिए अन्न के उत्पादन, बच्चों के लिए दूध की आपूर्ति, गायों के रख-रखाव, खेत में ही सब्जी व दालों का उत्पादन करने से किसान को आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त थी। गांव तथा समीपवर्ती कस्बे के हाट से उसकी अन्य प्रकार की जरूरतें पूरी हो जाती थीं। गांव में ही कुछ परिवार जूते, लकड़ी की वस्तुएं आदि का निर्माण करते थे। इन वस्तुओं को सुविधापूर्वक हाट में बेचा जा सकता था। यह सही है कि परिवहन की अपर्याप्त सुविधा के कारण विभिन्न गांवों में वस्तुओं का पारस्परिक व्यापार संभव नहीं था। इसके बावजूद स्वतंत्रता से पूर्व हमारे गांव अपनी आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते थे। इस अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी बात यह थी कि यह संतुलित थी और बाजार के उतार-चढ़ाव से मुक्त थी। उत्पादन का स्तर छोटा तथा बाजार की कुल मांग के अनुरूप बना रहता था। जैसे-जैसे भारत के शहरों में फैक्ट्री आधारित उत्पादन बढ़ने लगा, भारत की ग्रामीण तथा शहरी अर्थव्यवस्थाओं में मांग तथा आपूर्ति के बीच संतुलन बिगड़ना प्रारम्भ हो गया। वस्तुत; फैक्ट्री आधारित उत्पादन में जहां एक ओर बड़े स्तर पर पूंजी की जरूरत होती है, वहीं उत्पादन क्षमता का भी एक न्यूनतम स्तर निर्धारित होता है। इससे कम स्तर पर उत्पादक इकाई अस्तित्व में नहीं रह पाती। इसी कारण विभिन्न उत्पादक इकाइयों के लाभ के स्तर भी घटते-बढ़ते रहते हैं। साथ ही इनके शेयर मूल्य भी घटते-बढ़ते हैं। यही कारण है कि आज का दौर उतार-चढ़ाव का दौर है। इस विसंगति का भारत की परम्परागत अर्थव्यवस्था में कोई स्थान नहीं था। यह स्पष्ट कर देना उपयोगी होगा कि उस दौर में हमारी जीडीपी की वृद्धि दर कम रही, लेकिन संतुलित तथा विश्वसनीय थी। आज का दौर अन्तरराष्ट्रीय विषमताओं तथा विसंगतियों का दौर है। जहां एक जोत का का आकार अत्यंत छोटा होने के कारण, लाभप्रदता का स्तर कम है, वहीं सहायक गतिविधियां समाप्त होने के कारण कृषि उतार-चढ़ावों का शिकार हो रही है, विशेष रूप से जहां पर एक ही फसल उगाई जा रही है। यह राहत की बात है कि हाल के दशकों में भारत सरकार कृषि की त्वरित प्रगति के लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति गंभीर है। वर्ष 2025 तक कृषकों की आय को दोगुना करने के प्रयास प्रारम्भ कर दिए गए हैं। फिर भी हमें यह स्मरण रखना होगा कि कृषि से प्राप्त आय में वृद्धि काफी हद तक पानी की निर्भर करेगी। इसलिए कम पानी का उपयोग करने वाली फसलों पर अधिक से अधिक ध्यान देना भी जरूरी है। इस बात पर भी विचार करना होगा कि कम लागत में हम ग्रामीण उद्योगों का विकास करके भी कृषकों की आय को बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त समय में साबुन निर्माण, बिजली-नल मरम्मत, बढ़ईगिरी, जूता निर्माण जैसे कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देकर हम कृषक परिवारों की आय में वृद्धि के प्रयास कर सकते हैं। आज भी देश के अनेक भागों में साप्ताहिक हाट की परंपरा चल रही है। कृषक परिवारों द्वारा निर्मित वस्तुओं को इन साप्ताहिक बाजारों में बेचने की व्यवस्था की जा सकती है। राजस्थान में 2004 में मिशन ऑन लाइवलीहुड की स्थापना की गई थी जिसके अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं को कुटीर उद्योगों से सम्बद्ध प्रशिक्षण दिया गया था। यह तरीका उपयुक्त रहेगा। थोड़ा सा प्रशिक्षण हमारे ग्रामीण युवाओं को अतिरिक्त आय दिला सकता है। इसके लिए सरकारी स्तर पर गंभीरता से प्रयास होने चाहिए।

प्रो. सी.एस. बरला
(यह लेखक के अपने विचार हैं)

विधि सेवा स्मारिका
निर्देशिका-2024 का विमोचन

जयपुर। राजस्थान विधि सेवा परिषद की ओर से प्रकाशित चविधि सेवा स्मारिका एवं निर्देशिका-2024 का शासन सचिवालय परिसर में विधि मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने पुस्तक का विमोचन किया । विधि मंत्री ने पुस्तिका के विमोचन पर विधि सेवा परिषद के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि परिषद ने विधि सेवा से संबंधित बहुत उपयोगी पुस्तिका उपलब्ध करवाई है। इसमें विधि अधिकारियों की कार्य दक्षता में वृद्धि के लिए उपयोगी सामग्री समाहित है। विधि मंत्री ने बताया कि वर्तमान के डिजिटल युग में विधि से संबंधित सभी कार्यों तथा निर्देशों की जानकारी कप्यूटराइज्ड हो। साथ ही, विधि सेवा राज्य के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अतिआवश्यक है। विधि सेवा परिषद द्वारा निर्भीक होकर सही दिशा में विधि सलाह दी जाए जिससे शासन की पवित्रता बनी रहे और हमारे शासन पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगे। श्री पटेल ने बताया कि समय के अनुसार विधि में बदलाव होते रहते है। इसके लिए हमेशा सीखने व जागरूक रहने की आवश्यकता है तथा अधिक कार्य भार न हो, इसके लिए व्यर्थ के मुकदमों में भी कमी लायी जाए। विधि मंत्री ने विधि विभाग की कुछ समस्याओं पर चर्चा करते हुए कहा कि चिमिनिमम एक्जामिनेशन मैक्जिमम एपलॉयमेंटज का ध्येय रखते हुए विभाग में भर्ती संबंधी सुधार लाये जाए। इस दौरान प्रमुख शासन सचिव, श्री वीरेन्द्र कुमार जैन ने कहा कि शासन के हर क्षेत्र व हर स्तर पर विधि सेवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने विधि सेवा परिषद के सदस्यों से अनुरोध किया कि विधि के नए बदलावों को देखते हुए स्वयं को अपडेट रखे। साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का सकारात्मक उपयोग कर नए नियम-अधिनियम का ज्ञान अर्जित करते रहें। इस अवसर पर राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह, विधि सचिव श्री राजेश कुमार गुप्ता, वित्त सचिव श्री के.के.पाठक , परिषद के वरिष्ठ सलाहकार व अधिकारीगण उपस्थित रहे।

प्रदेश में कामधेनु बीमा योजना खटाई में, नई योजना का अता-पता नहीं

पशुपालकों के सिर से उठा 'बीमा कवच'

लंपी की चपेट में आ चुके हजारों पशुपालकों की अब नई योजना पर टिकी निगाहें

पुरुषोतम झा
Www.marwadkamitra.in

हनुमानगढ़. पशुपालकों के सिर पर वर्तमान में किसी तरह का बीमा कवच नहीं है। अपने रिस्क पर हजारों पशुपालक प्रदेश में पशुपालन व्यवसाय में जुटे हुए हैं। गत वर्ष राजस्थान सरकार ने सभी जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरू करके तीस-तीस पशुओं का बीमा करवाया था। सरकार स्तर पर बीमा प्रीमियम जमा करवाकर पीड़ित पशुपालक को प्रति दुधारू पशु की मौत पर चालीस-चालीस हजार रुपए का आर्थिक सहयोग दिया गया। परंतु इसके बाद प्रदेश में नई सरकार बनने पर इस योजना को अप्रत्यक्ष रूप से बंद कर दिया गया। इसका प्रमाण यह है कि योजना शुरू होने के करीब सवा साल बाद भी प्रदेश के किसी जिले में तीस से अधिक पशुओं का बीमा नहीं हो सका।

इस स्थिति में हजारों पशुपालक अपने रिस्क पर पशुपालन व्यवसाय कर रहे हैं। जबकि सरकार स्तर पर किसी तरह की बीमा योजना वर्तमान में प्रभावी नहीं है। इतना जरूर है राज्य सरकार की तरफ से 2024-25 की बजट घोषणा में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू करने की बात कही गई है। परंतु जमीनी तौर पर अभी इस योजना की ज्यादा जानकारी स्थानीय अधिकारियों के पास नहीं है। ऐसे हालात में पशुपालक हैरान व परेशान हो रहे हैं। दो वर्ष पहले लम्पी बीमारी की चपेट में प्रदेश में हजारों दुधारू पशु आ गए थे। हनुमानगढ़ जिले में करीब 3200 पशुओं की मौत हुई थी। इसमें करीब 1800 दुधारू पशु थे। इनको चालीस-चालीस हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई थी। लेकिन इसके बाद सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाने की बजाय इसको निपटाने में ज्यादा रुचि दिखाई। अब नई सरकार भी इस योजना का नाम बदलकर ही खानापूर्ति करने में जुटी हुई है। ऐसे हालात में लंपी का दर्द झेल चुके प्रदेश के हजारों पशुपालकों की आंखें अब नई मंगला योजना पर टिकी हुई है।

फैक्ट फाइल

- बीसवीं गणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन 5.68 करोड़ रही है, जो वर्ष 2012 में 5.77 करोड़ था।
- दो वर्ष पहले लपी बीमारी से हनुमानगढ़ जिले में करीब 3200 पशुओं की मौत हुई थी।
- पूर्व के बरसों में कामधेनु बीमा योजना के तहत पशुओं की मौत पर 40-40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई थी।

प्रदेश में इतने पशु

बीसवीं पशुगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन 5.68 करोड़ रही है। जो वर्ष 2012 में 5.77 करोड़ था। इस प्रकार 2019 में कुल पशुओं की संख्या में 1.66 प्रतिशत की कमी देखी गई। हनुमानगढ़ सहित प्रदेश के करीब-करीब सभी जिलों में पशुओं की संख्या में कमी देखी गई थी। बावजूद पशुपालन की दृष्टि से देश में राजस्थान का अहम स्थान है। तकनीक के जमाने में बैलगाड़ी व ऊंटगाड़े का चलन कम हो रहा है। दुधारू पशुओं के व्यापार पर भी कुछ नियम लागू हुए हैं। इसके अलावा बढ़ रही महंगाई के चलते भी पशुपालन व्यवसाय से लोगों का मोह भंग हो रहा है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह पशुपालकों को आर्थिक तौर पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क बीमा योजना शुरू करे।

नहीं है कोई गाइड लाइन

नए वित्तीय वर्ष में कामधेनु पशु बीमा योजना में अभी बीमा करने को लेकर गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। नई सरकार ने बजट घोषणा में मंगला योजना शुरू करने की बात कही है। लेकिन यह योजना कैसे लागू होगी, इसे लेकर हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। पशुगणना रिपोर्ट के अनुसार जिले में पहले की तुलना में पशुओं की संख्या में कमी आ रही है।

डॉ. हरीश गुप्ता,
संयुक्त निदेशक,
पशुपालन विभाग हनुमानगढ़

घर बैठे मारवाड़ का मित्र मंगाने के लिए भर कर भेजें

सदस्यता फॉर्म

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र हैं। समाचार पत्र में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबरों का प्रकाशन कर पाठकों तक अखबार की प्रति प्रेषण कर रहा है। मारवाड़ का मित्र समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांक का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है। अतः मुझे / हमें भी अंग्राकित पते पर मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र की प्रति डाक द्वारा भेजें।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 350/- ☐ दो वर्ष रु. 700/- ☐ तीन वर्ष रु. 1050/- ☐ छह वर्ष रु. 2100/-

डाक से नियमित रूप से इस पते पर मारवाड़ का मित्र भेजने के लिए DD / मनीआर्डर मारवाड़ का मित्र के नाम भेज रहा हूं।

नाम / संस्था का नाम.....
ग्राम..... पोस्ट.....
तहसील..... जिला.....
फोन..... पिन कोड.....
राशि (रुपए) ..... बैंक का नाम.....

अगर आप किसी कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजें. अगर आप सीधे बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो Marwadkamitra@gmail.com पर अपना पूरा नाम, फोन नंबर, भुगतान की राशि और Transaction id हमें मेल करें ताकि हम आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार प्रकट कर सकें.

Bank Account Details :
Name: Marwad ka Mitra
A/C No.: 11134027554
IFSC Code: RMGB0000134
Google / Phonepay 9602473302

सदस्यता हेतु → Mo. 9602473302, Marwadkamitra.in

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

संपादकीय/व्यवस्थापक कार्यालय - वैष्णव फार्म परावा, तहसील-चितलवाना जिला-जालोर 343041

बैंकों की ऋण और जमा राशि पर स्थिति पर एसबीआई ने जारी की विशेष रिपोर्ट

बुजुर्गों के भरोसे चल रहीं बैंकों की जमा स्कीमें

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली। बैंकों के खाते में जमा के प्रति युवा समुदाय का मोहभंग हो रहा है। एसबीआई की एक रिपोर्ट बताती है कि बैंकों में कुल जमा राशि का 47 प्रतिशत बुजुर्गों का है। युवा बेहतर रिटर्न के लिए निवेश के दूसरे विकल्पों जैसे शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड की तरफ आकर्षित हैं और यह आकर्षण यूं ही बने रहने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक शेयर बाजार के निवेशकों की औसत आयु सिर्फ 32 वर्ष है। 40 प्रतिशत निवेशकों की आयु 30 वर्ष से भी कम है। मार्च, 2014 में म्यूचुअल फंड में कुल निवेशित राशि 3.95 लाख करोड़ रुपये है जो वर्ष 2024 में 19.10 लाख करोड़ रुपये का हो गई है। मोटे तौर पर निवेशक वहीं जाएंगे, जहां उन्हें बेहतर रिटर्न मिलेगा। वित्त वर्ष 2023 में बैंक की जमा स्कीमों (तीन वर्ष की अवधि के लिए) पर ब्याज 5.45 प्रतिशत था जबकि देश के सभी म्यूचुअल फंड्स पर समग्र तौर पर रिटर्न 46.37 प्रतिशत, सीधे शेयर बाजार में निवेश करने पर रिटर्न की दर सिर्फ 0.72 प्रतिशत थी लेकिन वर्ष 2024 में यह रिटर्न (शेयर बाजार) बढ़कर 24.85 प्रतिशत हो गया। म्यूचुअल फंड्स पर निवेशकों को 40.16 प्रतिशत का रिटर्न मिला। जबकि इस साल तीन वर्ष की बैंक सावधि जमा स्कीमों पर 6.56 प्रतिशत का रिटर्न मिला।

3.95 लाख करोड़ रुपये थी 2014 में म्यूचुअल फंड में निवेशित राशि

19.10 लाख करोड़ रुपये का हो गई 2024 में म्यूचुअल फंड में निवेशित राशि

पहले भी ऋण और जमा में देखा जा चुका है अंतर

वित्त वर्ष 2022 के बाद से सरकारी बैंकों में जमा राशि में कुल 61 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जबकि ऋण वितरण की राशि में 59 लाख करोड़ करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। एक दशक की बात करें तो जमा राशि में 2.75 गुना तो ऋण की राशि में 2.8 गुना की वृद्धि हुई है। यह स्थिति पहली बार नहीं हुई है। पहले भी दो या चार वर्ष के लिए ऋण और जमा में इस तरह का अंतर देखा जाता रहा है। यह एक चक्र है। मौजूदा चक्र जून-अक्टूबर, 2025 तक समाप्त होने की उम्मीद है।

वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर की चिंता को भी किया खारिज

रिपोर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लेकर आरबीआई गवर्नर डा. शक्तिकांत दास की इस चिंता को भी खारिज किया है कि बैंकिंग सेक्टर में जमा राशि की वृद्धि दर सुस्त हो रही है, जबकि ऋण वितरण की रफ्तार तेज है। स्टेट बैंक के अर्थविदों की टीम ने कहा है कि बैंकों ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान जो जमा और ऋण की वृद्धि दर हासिल की है वह वर्ष 1951-52 के बाद सार्वधिक है। इस दौरान जमा राशि में कुल 15.7 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जबकि ऋण राशि का विस्तार 17.8 लाख करोड़ रुपये का रहा है।

अपेक्स बैंक में शासन सचिव, सहकारिता ने किया पौधारोपण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। सहकारिता शासन सचिव श्रीमती शुचि त्यागी ने ''एक पेड माँ के नाम'' राष्ट्रीय अभियान के तहत टोंक रोड स्थित राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) परिसर में पौधारोपण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि पृथ्वी माँ को सुरक्षित रखने के लिये सभी एक पौधा अपनी माँ के नाम से अवश्य लगायें। पौधे अपनों के प्रति प्रेम और माँ के लिये आदर के प्रतीक हैं। शासन सचिव ने आह्वान किया कि राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण को संरक्षित करने के लिये चलाये जा रहे ''एक पेड माँ के नाम'' अभियान में सभी को बढ़-चढकर भाग लेना चाहिये और दूसरों को भी इसके लिये प्रोत्साहित करना करें। उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व है कि हम जो पौधा लगायें उसकी कम से कम एक वर्ष तक सुरक्षा करें ताकि पौधा स्वयं पोषित होकर प्रकृति में स्वच्छ वायु का संचार कर सके। हमारी पीढ़ी की ओर से आने वाली पीढ़ी के लिये सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण सबसे अच्छी सौगात होगी और इसके लिये हम सभी को सतत् एवं समावेशी प्रयासों की आवश्यकता है। इस मौके पर श्री संजय पाठक, प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी समिति कर्मचारी यूनियन की पंजीकरण प्रक्रिया संपन्न

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राज्य में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कार्मिकों का प्रदेश स्तर पर नेतृत्व करने के लिए एक नए संगठन राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी समिति कर्मचारी यूनियन जयपुर के नाम से पंजीकरण करवाया गया है। जिसे श्रम विभाग राजस्थान की ओर से ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत पंजीकरण संख्या TU/2024/14/132550 प्राप्त हुई है। राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी समिति कर्मचारी यूनियन जयपुर के नाम से हनुमानसिंह राजावत की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया गया हैं। गौरतलब हैं कि गत 11 अगस्त को जयपुर में पक्स कर्मचारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, इस दौरान उपस्थित नेतृत्वकर्ताओं ने एक राय लेकर ग्राम सेवा सहकारी समिति में कार्यरत कर्मचारियों के हित में नया संगठन बनाने का निर्णय लिया था ।

कृषकों को 50 हजार का दिया जा रहा अनुदान

जयपुर। आधुनिक युग में खेती में रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। जिससे मृदा की उर्वरकता में कमी आ रही है। मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा वर्मी कंपोस्ट इकाई निर्माण की शुरुआत की गई है। इससे मृदा की जैविक व भौतिक स्थिति में सुधार लाया जा सकेगा। इससे मृदा की उर्वरकता एवं पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। रासायनिक उर्वरकों से खेती की बढ़ती हुई लागत को कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पारंपरिक खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जिससे फसलों को उचित पोषण मिलने पर उनकी पूर्ण वृद्धि होगी एवं किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।

दी सिरोही सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की 67वीं साधारण सभा संपन्न

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सिरोही । दी सिरोही सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की 67वीं साधारण सभा बैंक प्रशासक एवं जिला कलेक्टर श्रीमति शुभम चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई । साधारण सभा के दौरान बैंक प्रशासक एवं जिला कलेक्टर श्रीमति शुभम चौधरी ने बैंक के हिस्साधारक सदस्यों को संबोधित करते हुए बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अर्जित उपलब्धियों का वर्णन कर बैंक की प्रगति से अवगत कराया । जिसके पश्चात बैंक प्रशासक एवं जिला कलेक्टर की अनुमति से सीसीबी प्रबंध निदेशक पूनाराम चोयल ने एजेंडा वार सदन की कार्यवाही प्रस्तुत करते हुए कहा कि बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर 254 करोड़ 48 लाख का अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया गया, साथ ही, बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 74.73 लाख का लाभ अर्जित किया गया, इस दौरान हिस्साधारक सदस्यों द्वारा बैंक की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए बैंक से संबंद्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय विक्रय सहकारी समिति सहित अन्य सहकारी समितियां के विकास पर चर्चा की गई।

सीसीबी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 74.73 लाख का लाभ अर्जित करने के साथ ही वित्तीय वर्ष में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर 254 करोड़ का अल्पकालीन फसली ऋण कराया उपलब्ध

ब्याज अनुदान का डाटा पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश के समस्त केंद्रीय सहकारी बैंक को वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के ब्याज अनुदान और समय पर ऋण चुकारा करने वाले किसानों से संबंधित ब्याज सहायता क्लेम प्रस्ताव का डाटा किसान ऋण पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक की ओर से दिए गए है। इस संबंध में जारी पत्र के मुताबिक, भारत सरकार से मिलने वाले 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान क्लेम की राशि प्राप्त करने के लिए बैंकों को वित्तीय वर्ष 2022-23 का डाटा 15 सितम्बर तक एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 का डाटा 15 दिसम्बर तक किसान ऋण पोर्टल पर अपलोड करना हैं, वही, भारत सरकार की ओर से 2 वर्ष से अधिक समय से ब्याज अनुदान का डाटा किसान ऋण पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश निरंतर देने के बावजुद डाटा अपलोड नहीं होने के कारण शीर्ष बैंक ने कार्य-योजना बनाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही, निर्धारित अवधि में डाटा अपलोड नहीं होने की स्थिती में भारत सरकार से ब्याज अनुदान राशि में देरी तथा प्राप्त नहीं होने के संबंध में समस्त जिम्मेदारी सीसीबी की होने का हवाला पत्र में दिया गया है।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत पशुपालकों को पांच-छह महीने से नहीं मिली अनुदान राशि

आमदनी बढ़ाने का दिखाया सपना, अब फूटी कौड़ी भी नहीं

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । प्रदेश में सहकारी डेयरियों के प्रति पशुपालकों का रुझान बढ़ाने के लिए गत सरकार ने मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना शुरू की थी। इसमें पशुपालकों को सहकारी डेयरियों में दूध देने पर प्रति लीटर पहले दो तथा बाद में पांच रुपए अनुदान राशि जारी करने का निर्णय लिया गया, एक फरवरी 2019 को शुरू हुई उक्त अनुदान योजना के बाद निरंतर पशुपालकों को उक्त राशि मिलती रही है। परंतु प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद से राज्य की सभी 24 सहकारी डेयरियों में अनुदान योजना की स्थिति डांवाडोल हो रही है। हालत यह है कि करीब पांच-छह महीने से पशुपालकों को योजना के तहत फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है। इस स्थिति में अब पशुपालकों ने सहकारी डेयरियों को दूध देना बंद कर दिया है। जबकि प्राइवेट डेयरियों के पास खूब दूध जाने लगा है। लंबे समय तक यही स्थिति रही तो सरस डेयरियों को दूध मिलने में काफी दिक्कतें आ सकती है।

राहत के बाद अब आहत

राजस्थान सरकार की ओर से वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना शुरू की गई, इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा दूध बेचने पर पात्र लाभार्थियों को प्रति लीटर दूध पर पांच रुपए की अनुदान राशि प्रदान करने की व्यवस्था है। उक्त योजना के शुरू होने पर पशुपालकों को राहत मिली थी। बढ़ रही मंहगाई के बीच पशु आहार आदि खरीदने में मदद मिली। परंतु अब अनुदान राशि अटकने से पशुपालक आहत हो रहें हैं।

जिले पर नजर

जालोर जिले की बात करें तो यहां पर रानीवाड़ा डेयरी से करीब 577 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां जुड़ी हुई है। इनके माध्यम से प्रतिदिन दूध संग्रहण किया जा रहा है। जालोर, सिरोही और सांचौर जिले के करीब हजारों पशुपालक सीधे तौर पर डेयरी से जुड़े हुए हैं। जिले में करीब पांच-छह महीने से करोड़ों रुपए का अनुदान अटका हुआ है। इससे पशुपालक परेशान हो रहे हैं।

दो माह के ब्याज अनुदान का भार केंद्रीय सहकारी बैंकों पर थोपना अनुचित-आमेरा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । हाल ही में राज्य के सहकारिता विभाग ने गत रबी सीजन में वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों की वसूली अवधि 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी, इस विस्तारित अवधि के दौरान अल्पकालीन फसली ऋण वसूली पेटे देय 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान के रुप में 6 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय सहकारी बैंकों को वहन करनी पड़ेगी । इस निर्णय पर चिंता व्यक्त करते हुए ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्लाइज यूनियन, ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रांतीय महासचिव एवं सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने शासन सचिव सहकारिता विभाग एवं पंजीयक सहकारिता विभाग को ज्ञापन देकर सहकारिता विभाग के इस बैंक विरोधी निर्णय पर पुनर्विचार कर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार स्तर से ही वहन किए जाने की मांग रखी है । सहकार नेता ने कहा कि केंद्रीय सहकारी बैंक को रिजर्व बैंक के बैंकिंग लाइसेंस के तहत बैंकिंग अनुशासन में कार्य करना होता है, जिसमें सरकार के इस निर्णय से परेशानी पैदा होगी । रिजर्व बैंक के आर्थिक मानदंडो सीआरएआर की पालना में चूक होने से रिजर्व बैंक लाइसेंस पर भी संकट के बादल मंडरा सकते है।

राज्य सरकार का प्रायोजित बजट निर्णय ब्याज अनुदान

सहकार नेता ने बताया कि ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण योजना के तहत देय 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित बजट निर्णय है, साथ ही, रबी फसली ऋण की देय तिथी दो माह बढ़ाने का भी राज्य सरकार का ही निर्णय है, जबकि तिथि बढ़ाने के संबंध में केंद्रीय सहकारी बैंको से कोई प्रस्ताव एवं सहमति नहीं दी गई है, सरकार के इस तर्कहीन, अनुचित, अव्यवहारिक फरमान से राज्य के सहकारी बैंक आर्थिक रूप से कमजोर होने के साथ-साथ उनकी लाभप्रदता में कमी आएगी ।

सहकारी समितियों में आयोजित होंगे जागरूकता शिविर

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । सहकारिता विचारों के बारे में सहकारी समिति सदस्यों को जागरुक करने का संकल्प राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली ने लिया हैं, इसके लिए सहकारी प्रबंध संस्थान जयपुर के निदेशक डॉ. आर. के. शर्मा की ओर से पत्र के जरिए राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ सहकारी समितियों में शामिल पलसाना सहकारी समिति के निवर्तमान व्यवस्थापक महादेवसिंह ऐचरा को स्केलिंग अप ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत सीकर, नीम का थाना, राजसमंद नागौर एवं दूदू जिलों में सहकारिता के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का कहा गया है। इस दौरान इन जिलों की ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सदस्यों को सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ की गई प्रमुख पहलों, नई सहकारिता नीति, बहुउद्देशीय सहकारिता कानून, सहकारिता के समक्ष चुनौतियां एवं समाधान, सहकार से समृद्धि, सहकारी संस्थाओं के संगठनात्मक ढांचे की गतिविधियों एवं शर्तों से अवगत करवाया जाएगा ।

पंचायतीराज संस्थाओं में खत्म होगी सरपंच पति की प्रथा

जितेंद्र शर्मा
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली। देशभर की ढाई लाख पंचायतों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी 44 प्रतिशत है। यह आंकड़ा तेजी से हो रहे महिला सशक्तीकरण की कहानी सुनाता है, लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद भी गूंज रहे च्सरपंच पति और प्रधान पतिज् जैसे शब्द इससे खलल डाल रहे हैं। इस कुप्रथा के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर होने के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार ने सुधार की ओर प्रयास तेज किए हैं, उससे आशा कर सकते हैं कि भविष्य में यह प्रथा खत्म हो जाए। पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने 18 राज्यों में महिला प्रधानों की व्यावहारिक समस्याओं का अध्ययन कर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। अंतिम रिपोर्ट बनने के बाद इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाने की तैयारी में है। समाजसेवियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पिछले वर्ष सरपंच पति प्रथा को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। जुलाई, 2023 में कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर याचिकाकर्ताओं ने पंचायतीराज मंत्रालय को अपना प्रस्तुतीकरण दिया, जिसके बाद मंत्रालय ने सितंबर, 2023 में सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी सुशील कुमार की अध्यक्षता में दस सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन इस व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन कर सुझाव देने को कहा। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि कमेटी में शामिल विशेषज्ञों ने 18 राज्यों में पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की व्यावहारिक समस्याओं पर अध्ययन किया कि आखिर उन्हें प्रतिनिधि के रूप में अपने पति की ओट क्यों लेनी पड़ती है। अभी समिति ने अंतिम रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन अपने अध्ययन के कुछ प्रमुख बिंदु मंत्रालय से जरूर साझा किए हैं। समिति ने राजसमंद की एक महिला प्रधान के अनुभवों के आधार पर कहा है कि सिर्फ पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए कोई महिला सरपंच सामाजिक और सामुदायिक मान्यताओं को तोड़ना नहीं चाहती। छत्तीसगढ़ और बिहार की महिला सरपंचों से फीडबैक मिला है कि पितृसत्ता, परिवार और जाति संबंधी पूर्वाग्रहों के सामना करते हुए सरपंच के रूप में कामकाज संभालना आसान नहीं है। वहीं, सभी राज्यों से जो समान कारण मिला, वह यह कि प्रभावी ढंग से कामकाज करने के लिए महिला जनप्रतिनिधियों को अभी और अधिक क्षमतावान बनाने की बहुत आवश्यकता है। इस अध्ययन के आधार पर समिति ने जो सुझाव दिए हैं, उनमें प्रमुखता से कहा है कि निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के शासन और प्रबंधन संबंधी कौशल और क्षमता विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहल करनी होगी। शिक्षा व्यवस्था और सोच में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। स्कूल ऑफ प्रेक्टिस बनाकर सफल महिला जनप्रतिनिधियों से प्रशिक्षण दिलाया जाए।

प्रमुख सुझाव

सरपंच पति प्रथा खत्म करने के उद्देश्य से राज्यों के लिए आदर्श कानून का प्रारूप बनाया जाए।

क्या राज्य महिलाओं के लिए पंचायत सचिव पद पर 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू कर सकते हैं?

मैन्युअल उन सभी भाषाओं में बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसे अशिक्षित महिलाएं भी समझ सकें।

भ्रष्टाचार भी एक बड़ी चुनौती ; बिहार और राजस्थान में अध्ययन करते हुए समिति ने पाया है कि महिला सरपंच कई चुनौतियां महसूस करती हैं, उनमें भ्रष्टाचार भी एक प्रमुख है। दरअसल, उन्हें कई चेक पर हस्ताक्षर करने होते हैं, निविदाएं स्वीकृत करनी होती हैं, तब उन्हें अनजाने में भी हुई गलती के कारण जेल जाने का डर सताता है। ऐसे में वह अपने पति पर ही भरोसा करते हुए उन पर निर्भर रहने में सुरक्षित महसूस करती हैं।

मारवाड़ का मित्र

हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

सांचौर, रविवार, 1 सितंबर 2024

4

RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136

Post Reg No. R.J./SRO/9657/2023-25

फलोदी जिले में चार नवीन सहकारी समितियों का होगा गठन

जयपुर। प्रदेश के फलोदी जिले में चार नवीन बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा, इसके लिए सहकारिता विभाग के पंजीयक कार्यालय की ओर से मंगलवार को प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक, फलोदी जिले की राणेरी समिति में से सोनलपुरा, सांवरीज में से मयाकोरियां, बावड़ी कलां में से उदाणियों की ढाणी, छीला में से डेरियों की ढाणी में बहुउद्देशीय सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। इस संबंध में रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से सहकारी समिति गठन के लिए स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा 5 वर्ष हेतु भवन उपलब्ध कराने के साथ ही, राजस्थान राजस्व विभाग के नियम 5(1) के अनुसरण में गोदाम निर्माण हेतु 1500 वर्ग मीटर का निःशुल्क भूखंड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, वही, नवगठित बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के सृजन एवं संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की आर्थिक सहायता स्वीकृत नहीं की जाएगी।

ग्रामीण विकास में सहकारी बैंकों की अहम भूमिका

19 राज्यों के प्रत्येक जिले को कवर करने के लिए खुलेंगे जिला स्तर पर नए केंद्रीय सहकारी बैंक

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली। ग्रामीण विकास की सबसे प्रमुख आधारशिला सहकारिता हैं, देश में सहकारी आंदोलन को गति प्रदान करने के निरंतर प्रयास जारी हैं, साथ ही, सहकारिता का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के अनेक प्रयाय किए जा रहें है। गत दिनों सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी बैंकिंग से संबंधित मुद्दों और मंत्रालय द्वारा की गई पहलों को लागू करने की गहन समीक्षा की, इस दौरान सहकारी बैंकों से जुड़े हितधारकों से विचार-विमर्श किया गया। मुंबई स्थित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के प्रधान कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में केंद्रीय सहकारिता सचिव ने बैंकरों से मुलाकात कर उनकी राय जानी, बैठक में सरकार की ओर से उठाए सुधारात्मक कदमों को समयबद्ध तरीके से लागू करने और मंत्रालय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। समीक्षा बैठक में देश के 19 राज्यों के प्रत्येक जिले को कवर करने के लिए नए जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखाएं खोलने और ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा रूपे क्रेडिट कार्ड जारी करने, सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के कार्यान्वयन का ब्यौरा समीक्षा बैठक में लिया गया । दरअसल, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित एक ग्रामीण सहकारी बैंक है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में जिला स्तर पर संचालित होता है। इस बारे में नाबार्ड ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अनुरोध किया था कि वह आरबीआई के वित्तीय रूप से मजबूत और अच्छी तरह से प्रबंधित मानदंडों को पूरा करने वाले सभी पात्र अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति देने के फैसलों को तेजी से आगे बढ़ाएं।

अन्न भंडारण योजना को आगे बढ़ाने के लिए बैंकों से दिए जा रहे ऋण

अनाज भंडारण योजना के तहत 52 पैक्स का चयन

समीक्षा बैठक में महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससी बैंक) के प्रशासनिक बोर्ड अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने के साथ ही देश भर में सहकारिता को मजबूत के लिए उठाये कदमों का विस्तार से जिक्र किया। सहकारी क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े अनाज भंडारण के कार्यान्वयन रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई। सहकारी क्षेत्र के दिग्गजों के बीच उच्च भंडारण क्षमता के सहकारी गोदाम बनाने के मसले पर विमर्श किया गया। मालूम हो कि इसके लिए पहले से ही 52 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को चुना गया है। इस बाबत इन पैक्स को गोदाम बनाने के लिए एमएससी बैंक द्वारा सीधे वित्त की सुविधा दी जा रही है।

यूसीबी को नई शाखाएं खोलने का अधिकार

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की पहल से केंद्र सरकार के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए देश में 1,514 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को मजबूत करने के लिए चार महत्वपूर्ण पहल करते हुए बदलाव किए गए हैं। इसके तहत शहरी सहकारी बैंक कॉमर्शियल बैंकों की तरह लोन लेने वालों के साथ एकमुश्त निपटान एग्रीमेंट कर सकेंगे। इन्हें आरबीआई की पूर्व अनुमति के बिना ही हर साल नई शाखाएं खोलने का अधिकार भी मिल गया है। इससे सहकारी बैंकों को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिली है।

कृषि विज्ञान केन्द्र केशवना में विभिन्न किस्मों के 20 पौधों का किया गया रोपण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर। कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसन्धान संस्थान, जोधपुर के विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम अभियान को गति देते हुए कृषि विज्ञान केंद्र केशवना में मातृ वृक्ष बेर की थाई बेर एवं भूराज किस्म के 20 पौधों का पौधारोपण कर उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर केंद्र की प्रसार विशेषज्ञ श्री मती सुमन शर्मा ने पेड़ों की प्रकृति की निर्भरता से अवगत करवाते हुए वृक्ष को जीवन का आधार बताया। केंद्र के उद्यान विशेषज्ञ डॉ पवन कुमार पारीक ने प्रकृति के संतुलन के लिए पौधारोपण को आवश्यकता बताया। पौधारोपण के दौरान शस्य विज्ञान विशेषज्ञ बिरम सिंह गुर्जर, आनंद कुमार, नाहर सिंह देवरा, भूपेन्द्र सिंह व पिरा राम सहित केन्द्र के कर्मचारी उपस्थित रहे।

ऋण और जमा के बीच अंतर पर नजर रखें बैंक : आरबीआइ

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली, बैंकों को ऋण और जमा वृद्धि के बीच अंतर पर सावधानीपूर्व नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि भविष्य में यह समस्या एक चुनौती बन सकती है, जिससे नकदी की दिक्कत पैदा हो सकती है। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, बैंकों को महत्वाकांक्षी युवा भारतीयों की निवेश रणनीतियों में आ रहे बदलाव पर फोकस करना चाहिए। बैंकों को जमा बढ़ाने के लिए न केवल नए उत्पाद और सेवाएं पेश करनी चाहिए बल्कि इसके लिए अपने विशाल शाखा नेटवर्क का भी उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सकारात्मक बात यह है कि बैंक इन दिनों आकर्षक दरों पर बुनियादी ढांचे के बांड के जरिये धन जुटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के कारण ऋण वृद्धि में तेजी आई जबकि जमा बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर भौतिक चैनलों का इस्तेमाल करना पड़ता है। दास ने कहा कि अगर मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहती है तो रेपो रेट में कमी का फैसला लिया जा सकता है। जुलाई में खाद्य पदार्थों की कीमतों में आई कमी पर्याप्त नहीं थी। दास ने कहा, च्हमें विश्वास होना चाहिए कि मुद्रास्फीति चार प्रतिशत के आसपास रहेगी। इसके लिए हमें धैर्य रखना होगा।

लगातार दूसरे साल शक्तिकांत दास शीर्ष केंद्रीय बैंकर बने ; आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने लगातार दूसरे साल वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया है। उन्हें ए प्लस रेटिंग दी गई है। डेनमार्क के क्रिश्चियन केटल और स्विटजरलैंड के थामस जार्डन को भी केंद्रीय बैंकरों की ए प्लस श्रेणी में रखा गया है।

सहकार भवन के लिए जमीन आवंटन की कब होगी कवायद

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर। केंद्र सरकार की सहकारिता मंत्रालय गठन की पहल के बाद से सहकार का महत्व बढ़ा हैं, परन्तु जिले में सहकारी संस्थाओं के चुनाव से लेकर गठन तक की प्रक्रिया संपन्न करने वाला कार्यालय किराए के भवन में संचालित हैं, यानि कि उप रजिस्ट्रार कार्यालय के पास खुद का भवन तो दूर, जमीन आवंटन तक नहीं हो पाई है। जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों से जुड़े किसानों को एक छत के नीचे ही सभी सुविधाएं देने की योजना कागजों में खुब दौड़ रही हैं, लेकिन जिला मुख्यालय पर सहकार भवन के लिए जमीन का आवंटन की अभी तक कोई कवायद नहीं हैं, जबकि जिले में सहकारी साख आंदोलन से जुड़े सुत्र निरतंर जिला मुख्यालय पर सहकार भवन के लिए जमीन चिह्नित कर उपलब्ध कराने का अनुरोध निरंतर उच्च अधिकारियों से कर रहें है, और तो और इस संबंध में रजिस्ट्रार कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जिला मुख्यालय पर सहकार भवन निर्माण में जमीन आवंटन के संदर्भ में मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के बजाए रजिस्ट्रार कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी सुरेंद्रसिंह द्वारा आधी-अधुरी जानकारी आर.टी.आई पोर्टल पर देकर इतिश्री कर ली गई है। फिलहाल जालोर जिले में उप रजिस्ट्रार कार्यालय किले की घाटी में, तो स्पेशल ऑडिटर कार्यालय नगर परिषद के सामने पुराने मकानों में किराए पर संचालित हो रहें हैं ।

एक ही जगह मिलती हैं सुविधाएं

सहकार भवन में सहकारिता विभाग के सभी कार्यालय, सहकारिता बैंक, सभाकक्ष, सहकारी समितियों द्वारा निर्मित वस्तुओं के विपणन सह प्रदर्शनी केंद्र बनाए जाते हैं, सहकार भवन में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उत्पादित वस्तुओं की बिक्री व प्रदर्शनी के लिए स्टॉल भी लगाए जा सकते है, सहकार भवन में जिला सहकारिता पदाधिकारी से लेकर विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के कार्यालय होते हैं, साथ ही, सभाकक्ष भी होता हैं, जिसमें सहकारिता से संबंधित प्रशिक्षण, सभा, बैठक आदि कार्य एक ही जगह संपन्न किए जाते है।

गोशालाओं को मिलने वाले अनुदान के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई

जयपुर, *राज्य के विभिन्न जिलों में अतिवृष्टि एवं मुख्यमंत्री वृक्षारोपण कार्यक्रम की क्रियान्विति के कारण जिलों द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर पशुपालन और गोपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने गौशालाओं को वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम चरण की अनुदान सहायता राशि हेतु समय सारिणी में परिवर्तन के निर्देश दिए। कई गोशाला संचालक तकनीकी कारणों से अंतिम तिथि तक अनुदान के लिए आवेदन नहीं कर सके थे। ऐसी स्थिति में गोशाला संचालकों की सुविधा के लिए उनके आग्रह पर भी मंत्री श्री कुमावत ने गोपालन विभाग को आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने के निर्देश दिए जिसके आधार पर विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। पात्र गौशालाओं द्वारा वर्तमान में गोपालन वेब पोर्टल पर आवेदन आगामी 5 सितंबर तक अपनी एसएसओ आई. डी. के माध्यम से*

मारवाड़ का मित्र हिन्दी पाक्षिक

विज्ञापन एवं समाचारों के लिए संपर्क करें

Website ; Www.Marwadkamitra.in

Mo. 9602473302, 7976323829

GMail.ID.marwadkamitra@gmail.com

कृषि जिंसों के क्रय-विक्रय पर मंडी व कृषक कल्याण शुल्क संग्रहित किये जाने का प्रावधान

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कृषि उपज मण्डी समिति जालोर के सम्पूर्ण कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में स्थित मंडियों के अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों से अधिसूचित कृषि जिसों का क्रय-विक्रय करने पर मंडी शुल्क व कृषक कल्याण शुल्क संग्रहित किये जाने का प्रावधान किया गया है। श्री कान्हड़देव कृषि उपज मण्डी समिति जालोर के सचिव कल्याणसिंह भाटी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी संशोधन अधिनियम 2022, कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 17, 17-क तथा नवीन धारा 17-ख के संबंध में विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग, (ग्रुप-2) द्वारा 19 जुलाई, 2024 को जारी अधिसूचना के तहत संशोधन किया गया है। संशोधन के तहत धारा 17, 17-क के तहत कृषि उपज मण्डी समिति जालोर के सम्पूर्ण कृषि उपज मण्डी क्षेत्र मुख्य मण्डी के साथ ही गौण मण्डी क्षेत्र में कार्यरत अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों द्वारा अधिसूचित कृषि जिंसों का क्रय-विक्रय करने पर कृषि जिन्स मोटा अनाज यथा-ज्वार, बाजरा तथा जीरा व ईसबगोल पर 0.50 रूपया, तिलहन पर 1.00 रूपया तथा शेष अन्य समस्त अधिसूचित कृषि जिंसों पर 1.60 रूपया प्रति सैकड़ा की निर्धारित दर से मण्डी शुल्क तथा समस्त अधिसूचित कृषि जिंसों पर 0.50 रूपया प्रति सैकडा की दर से कृषक कल्याण शुल्क संग्रहित किये जाने का प्रावधान लागू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त नवीन धारा 17-ख के तहत मुख्य तथा गौण मण्डी प्रांगणों की सीमाओं में कार्यरत अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों द्वारा क्रीत-विक्रीत गैर अधिसूचित कृषि उपज और खाद्य उत्पादों पर राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विर्निदिष्ट की गई दर के अनुसार विहित रीति से उपयोक्ता प्रभार संग्रहित किया जावेगा।

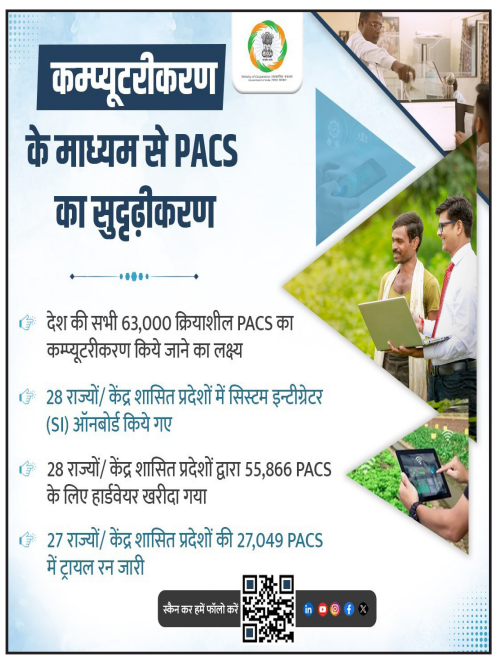

किसान की आय दोगुनी करने में मील का पत्थर साबित होगी सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना - आमेरा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, राज्य सरकार के सहकारिता मंत्री ने राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल का शुभारंभ किया, यह पोर्टल राज्य सरकार की बजट घोषणा की क्रियान्वित में लांच किया गया है, इसके तहत प्रदेश के 5 लाख पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस निर्णय का स्वागत करते हुए ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्पलाइज यूनियन एवं ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रांतीय महासचिव, सहकारी साख समितियां एम्पलाइज यूनियन के प्रान्तीय अध्यक्ष एवं सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने कहा कि भारत सरकार की किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में यह योजना मील का पत्थर साबित होगी । उन्होंने कहा कि इस योजना से किसान, गौपालक स्वावलंबी आत्मनिर्भर व समृद्ध होगा, इसके साथ ही, सहकार नेता ने सीसीबी एवं पैक्स कर्मियों से इस योजना को ज़मीनी स्तर लागू करने के लिए कर्मठता से कार्य करने का आह्वान किया हैं।

समय पर हो ब्याज अनुदान भुगतान

सहकार नेता आमेरा ने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में सीसीबी, पैक्स को आर्थिक मजबूती प्रदान करने एवं उत्साहपूर्वक कार्य करने की दृष्टि से ब्याज अनुदान का भुगतान समय पर करने या अग्रिम प्रामाणिक बजट व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरुरत जताई है। साथ ही, सहकार नेता ने सहकारिता मंत्री से ब्याज मुक्त फसली ऋण का बकाया ब्याज अनुदान भी सरकार से समय पर दिलवाने की अपेक्षा की है।

1 सितबर से 450 रूपये में उपलब्ध करवाया जायेगा गैस सिलेण्डर

जालोर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने वाले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) लाभार्थियों को 1 सितम्बर से गैस सिलेंडर 450 रूपये में मिल सकेगा। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा लंबे समय से 450 रूपये में सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए एनएफएसएस लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन कार्य किया जा रहा हैं तथा वर्तमान में सीडिंग का कार्य ई-मित्र व उचित मूल्य दुकानों पर स्थापित पोस मशीन के माध्यम से किया जा रहा हैं।

चर्म प्रशिक्षण के लिए दस्तकारों से 12 सितबर तक आवेदन पत्र आमंत्रित

जालोर। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र द्वारा वर्ष 2024-25 में चर्म प्रशिक्षण (लेदर गुड्स) के प्रशिक्षण के लिए 12 सितम्बर, 2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक संग्रामराम देवासी ने बताया कि आयुक्त उद्योग राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार जिले में शीघ्र ही चर्म प्रशिक्षण (लेदर गुड्स) प्रारंभ किया जायेगा। यह प्रशिक्षण अनुसूचित जाति के 20 अभ्यर्थियों को दो माह के लिए दिया जाएगा। विभाग द्वारा मास्टरक्राफ्ट मैन/हेल्पर का भी चयन किया जायेगा।

प्रदेश में 5 लाख नए किसानों को ऋण उपलब्ध कराने की सरकार ने की थी बजट घोषणा

खरीफ सीजन में फसली ऋण से वंचित रह गए 30 फीसदी किसान

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बाड़मेर। सीमावर्ती जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से पंजीयन कराने के पश्चात ब्याज मुक्त फसली ऋण प्राप्त करने के लिए नए किसानों को शाखा और सहकारी समिति मुख्यालय के बीच चक्कर काटने के बाजवुद खरीफ सीजन के फसली ऋण से वंचित होना पड़ा हैं, जबकि सरकार की बजट घोषणा के बाद विभाग द्वारा नए किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराने को लेकर प्रतिदिन आदेश निकाले जा रहें थे, परन्तु बाड़मेर केंद्रीय सहकारी बैंक ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और फंड की उपलब्धता के अनुसार ऋण देने की बात कर जिले के नए पंजीयन कराने वाले किसानों को गुमराह किया, दरअसल, इस वित्तीय वर्ष में बाड़मेर एवं बालोतरा जिले में 15618 नए किसानों ने अल्पकालीन फसली ऋण प्राप्त करने के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से पंजीयन करवाया था, लेकिन इनमें से खरीफ सीजन ऋण वितरण की निर्धारित तिथि तक 11 हजार किसानों को 24 करोड़ का ऋण मुहैया हो पाया है। औसतन प्रत्येक किसानों को 22 हजार रुपए का ही ऋण मिला है। वही, ऐसे में 30 फिसदी से ज्यादा नए किसान खरीफ सीजन के ऋण से वंचित रह गए हैं।

कार्यालय समय में सोनड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति पर लटकता ताला

15618 नए किसानों ने फसली ऋण प्राप्त करने के लिए करवाया पंजीयन

11120 किसानों को ही 24.77 करोड़ का ऋण दिया

30 फिसदी से ज्यादा किसान खरीफ सीजन के फसली सहकारी ऋण से रहें वंचित

अवधिपार ऋण वसूली शुरु हुई नोटिस प्रक्रिया

जिले में राज्य सरकार की नए किसानों को ऋण वितरण करने की बजट घोषणा की क्रियान्वित करने बजाए सीसीबी अधिशासी अधिकारी की ओर से सर्वाधिक अवधिपार ऋणों का बोझ अपने कंधो पर ढो रही सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को अवधिपार ऋण बढ़ोतरी के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, साथ ही, स्पष्टीकरण पत्र की प्रति संबंधित सहकारी समिति अध्यक्ष को भेजकर सहकारी समिति में बकाया चल रहें अवधिपार ऋण राशि की वसूली समय पर नहीं करने वाले समिति व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक के विरुद्ध व्यवस्थापकीय सेवानियम अंतर्गत कार्यवाही कर सीसीबी के प्रधान कार्यालय को सूचना भेजने के निर्देश पत्र के माध्यम से दिए जा रहें है। गौरतलब हैं कि करोड़ो की कर्जमाफी के पश्चात भी सहकारी समितियों में अवधिपार ऋणों में बढ़ोतरी होना अप्रशिक्षित लोगो को प्रस्ताव प्रणाली के सहारे सहकारी समितियों में दिए गए वित्तीय प्रभार का परिणाम है,

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक एवं मुद्रक प्रकाश वैष्णव द्वारा वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स, वैष्णव फार्म परावा 343041 जिला-सांचौर (राज.) से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर से प्रकाशित। संपादक। मो. 9602473302। नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी। (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।